भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2103
(28 जुलाई, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

शिमला में ग्रामीण सड़कों का निर्माण

2103. श्री के. सी. त्यागी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री दिनांक 7 जुलाई 2014 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 108 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले की चिरगांव तहसील में शिरोली-बंथल और जलवारी-कैलु सम्पर्क मार्ग प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के मानदण्डों को पूरा नहीं करता है;

(ख) क्या सरकारी जलवारी-कैलु सम्पर्क मार्ग को 'नाबार्ड' (एनएबीएआरडी) से सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत सम्मिलित करेगी;

(ग) क्या शिरोली-बंथल से सम्पर्क मार्ग को दो वर्ष पूर्व स्वीकृति प्रदान की गई थी किन्तु ठेकेदार की लापरवाही की वजह से इसका आज की तारीख तक भी निर्माण नहीं हो सका है;

(घ) क्या बदियारा-नांदला सड़क की रिमेटलिंग को 2011-12 के दौरान स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी किन्तु तीन वर्षों में केवल पड़ाव का हिस्सा ही पूरा हो पाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उन ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) : हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दोनों सड़कों की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:-

1. **शिरोली-बंथल:** यह सड़क पीएमजीएसवाई के मानदंडों को पूरा नहीं करती है।
2. **जलवारी-कैलु:** यह सड़क भी पीएमजीएसवाई के मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

(ख) : चूंकि ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय है; नाबार्ड सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत जलवारी-कैलु संपर्क मार्ग को शामिल करने का मामला हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उठाया जाए।

(ग) : राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि शिरोली-बंथल संपर्क मार्ग पीएमजीएसवाई रोड़ नहीं है।

(घ) और (ङ) : राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि पीएमजीएसवाई के तहत बदियारा-नांदला सड़क पहले ही वर्ष 2003-04 के दौरान बन चुकी है। राज्य सरकार ने इसके अतिरिक्त यह जानकारी भी दी है कि पांच वर्ष के लिए इस सड़क के रखरखाव की जिम्मेवारी वर्ष 2008-09 के दौरान खत्म हो चुकी है और राज्य सरकार 6.8 कि.मी. लम्बाई वाली सड़क पर पुन: कोलतार बिछाने का कार्य कर रही है, इसमें से 4 कि.मी. तक यह कार्य पूरा हो चुका है।

*****